डोम जाति के कल्याण से सम्बन्धित सरकारी प्रयास

यद्यपि आधुनिक भारत में जाति और जनजाति के सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने में परिवर्तन की नवीन शक्तियों जैसे औद्योगीकरण, नगरीकरण, यातायात और संचार के साधनों का प्रसार, शिक्षा का प्रसार, सहभागी राजनीतिक व्यवस्था, सम्प्रेषण के साधनों का विस्तार आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। तथपि कल्याणकारी कार्यक्रम की दिशा में सरकार के द्वारा उठाये गये इस क्षेत्र में उल्लेखनीय महत्व रखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उनके संवैधानिक व वैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया गया है। संविधान अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरूध केवल जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्यधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में समस्त नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 के अनुसार राजनिधि द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक का धर्म, प्रजाति तथा भाषा के आधार पर वंचित न किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय व सब प्रकार के शोषण से उनका सरंक्षण करेगा। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करने सार्वजनिक स्थलों पर अस्पृश्यता का आन्वरण कानून द्वारा निषिद्ध और दण्डनीय बना दिया गया।

अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण से सम्बन्धित सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, राजनीतिक आरक्षण, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व, शैक्षणिक व आर्थिक सुविधा सम्बन्धित नीतियों और कार्यक्रम है। संविधान के अनुसार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में इन लोगों के लिए लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में संविधान लागू होने से 20 वर्ष की अवधि हेतु (25 जनवरी, 1970तक) स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। इस अवधि को संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2000 तक बढ़ा दिया गया था। जिसे पुन: एक नवीन संशोधन के द्वारा 2010 तक सुरक्षित कर दिया गया है। लोक सभा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 79 स्थान सुरक्षित हैं जिनमें उत्तर प्रदेश में 18 स्थान हैं। राज्य क विधान सभाओं में भी अलग-अलग राज्यों के

स्थान सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार सुरक्षित सीटों की संख्या 89 है।

26 जनवरी 1950 को केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया कि 15 प्रतिशत नियुक्ति खुली प्रतियोगिता द्वारा भरी जाने वाली सेवाओं में तथा 16.7 प्रतिशत अन्य सेवाओं में नियुक्ति इन जाति समूह की होगी। नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आयु सीमा में छूट, योग्यताओं के मानदण्ड में रियायत आदि सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त 15 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने का सिद्धान्त उन नौकरियों पर भी लागू किया गया है जो केवल पदोन्नति तथा विभागीय उम्मीदवारों की प्रतियोगिता मूलक परीक्षा द्वारा भरी जाती है। कुछ राज्य सरकारों ने स्वापन्तशासी निकायों के लिए भी इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की है। जनवरी 1985 तक भारत सरकार के सेवा में तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या 619986 थी।

अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को शिक्षा सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण सुविधायें प्रदान की गयी हैं। निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, पुस्तकीय सहायता, प्रवेश की सुविधा आदि मुख्य है। इलाहाबाद, दिल्ली, मद्रास, कानपुर तथा जबलपुर में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधार्थियों के लिए केन्द्रीय लोक

सेवा आयोग से सम्बन्धित परिक्षाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मेडिकल, इन्जीनियरिंग तथा अन्य प्रौद्योगिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की गयी है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम मार्च 1975 में स्थापित की गयी है। निगम के उद्देश्य के अन्तर्गत राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक विकास करना, डाक्टरी, इन्जीनियरिंग, वकालत, आडिटेस्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेड या इससे सम्बन्धित व्यवसाय के लिए सस्ती ब्याज पर ऋण दिलाना। इनको टैम्पो, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा, टैक्सी या अन्य वाहन के लिए जिसका व्यवसाय में किया जाय, ऋण की जमानत लेना, कृषियन्त्र उद्योग व्यापार आदि के व्यक्तिगत प्रतिभूति अथवा व्यापारिक संस्थान के ऐसे समेन्ट पर ऋण दिलाना। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का उद्योग लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्पष्ट प्रसारित किये गये हैं कि कम ब्याज पर 6500 रूपये तक बिना सम्पत्ति की जमानत के ऋण उपलब्ध कराया जाय। विभिन्न बैंकों से इस डी0आर0आई0 योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाता है।

B.S. Purvanchal University Vivekanand Central Library Estd. 1999 Jaunpur U.P.

डोम जाति के कल्याण से सम्बन्धित प्रगति का अवलोकन तथा समुचित सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के कमिश्नर की नियुक्ति की है जिनके द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण सम्बन्धी भारत सरकार की नीति के दो मूल स्तम्भ है। प्रथम यह देखना कि देश के सामान्य सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों से अनुसूचित जाति के सदस्यों को लाभ प्राप्त हों और द्वितीय अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पृथक और विशेष नीतियों और कार्यक्रमों का समान स्थिति प्राप्त कर सकें। इस दृष्टि से उठाये गये कार्यक्रमों में शैक्षणिक कल्याणकारी कार्यक्रम का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है।

डोम जाति से सम्बन्धित अध्ययनों का सर्वेक्षण

Chitnis, 1974: The Educational Problems of Scheduled Castes and Tribe Collage Student i Maharashtra.[63]

इस अध्ययन का उददेश्य (1) राज्य के शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की स्थिति का अध्ययन करना। (2) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का समान्य विद्यार्थियों से तुलना करना। (3) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की कठिनाईयों, बाधाओं और उनके प्रति किये जाने वाले भेद-भाव का अध्ययन करना है।

Duby, S.M. (1974) The Study of Scheduled Caste and Scheduled Trib Collage, Student in Assam:[64]

यह अध्ययन आसाम के अनुसूचित जाति के कालेज विधार्थियों के सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए और यह देखने के लिए किस प्रकार शिक्षा उनकी आकांक्षाओं, उपलब्धियों, जीवनशैली, सामाजिक क्रिया-कलापों में सहभागिता दृष्टिकोण सामाजिक स्थिति इत्यादि को प्रभावित कर रहा है।

Gangrade, K.D. (1974): Educational Problems of the Scheduled Castes in Haryana(Collage Student)[65]

यह अध्ययन हरियाणा राज्य के 215 कालेज स्तर के अनुसूचित जाति के विधार्थियों और 45 कालेज अध्यापक से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। 4 जिले के 16 कालेज में इनका चयन किया गया है।

उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि (1)अनुसूचित जाति के विधार्थी अपने सामाजिक पृष्ठभूमि की सीमितताओं के कारण संविधान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा सके हैं।

(2) इन विधार्थियों का पारिवारिक परिवेश उनके विकास के लक्ष्य के अनुकूल नहीं है। अधिकांश विधार्थियों के माता-पिता तथा परिवार के सदस्य अशिक्षित हैं। इन विधार्थियों का केवल 1/10 वां भाग शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों में रूचि रखता है और 2/3 भाग विधार्थियों ने समाज में उन पर किये जाने वाले खराब बर्ताव के प्रति शिकायत की है। (3)अनुसूचित जाति के विधार्थियों का प्रतिशत सामान्य विधार्थियों की तुलना में अत्यन्त निम्न हैं।

Pimply, P.N., (1980) A Profit of Scheduled Caste Student. Panjab University Press. Chandigarh:[66]

पिम्पली 1980 में पंजाब के अनुसूचित जाति के छोत्रों के शैक्षणिक जीवन सामाजिक दृष्टिकोण व्यवसायिक अभिप्रेरणा, राजनीतिकरण आदि का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति के छात्रों की सामाजिक-आर्थिक परस्थिति में सुधार लाया जाय। चूंकि शिक्षा ही आधुनिक व्यवस्था में इन जातियों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति में मूलभूत परिवर्तन करने में समक्ष है। अत: इस दिशा में उन्हें स्वयं प्रयास करना होगा। अनुसूचित जातियों को संरचनात्मक परिवर्तन के लिए शिक्षित होना होगा और अपने पिछड़ेपन के मूल कारणों के प्रति जागरूक होना होगा। चूंकि सरकारी नौकरियां सीमित हैं और शिक्षित अनुसूचित

जाति के सदस्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है, इस लिए सरकार को निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए प्रयास करना होगा। यदि सरकार इस दिशा में असफल हुई तो राजनीतिक दृष्टिकोण से जटिल स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। पंजाब और बिहार में इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। जब तक अनुसूचित जाति के लोग अन्य जातियों के समक्ष नहीं हो जायेंगे तब तक उनकी निर्योग्यतायें यथावत रहेंगी, लेकिन जातिहीन एवं वर्गहीन समाज की परिकल्पना न तो निर्मित की जा सकती है, व्यवहार में इस कोटि का समाज न तो कहीं है और न ही इस दिशा में गम्भीर प्रयास किया जा रहा है।

Usha Rao, N.J.(1981) Deprived Caste in India, Chugh Publication, Allahabad:[67]

उषा राव (1981) ने भारत के अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में किये गये अपने अध्ययन के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक परिस्थिति, व्यवसायिक प्रतिमान और अन्तर्जातीय संरचना का विश्लेषण किया है। अनुसूचित जाति के सदस्यों के सम्बन्ध में उषा राव का कथन है कि इनका युक्ति संगत वर्गीकरण किया जाना चाहिए। माला, अरण्य, वन्दी, जंगली, कपाली, मास आदि जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में

सूचीबद्ध किये जाने की संस्तुति करते हैं। इनका कथन है कि अधिकांश अनुसूचित जातियां गांव में निवास करती हैं, और उनके अधिकांश श्रम योग्य सदस्य कृषि श्रमिक कुटीर उद्योग और सहायक अप्रवास क्रिया-कलापों में लगे हुए हैं। केवल नगरीय क्षेत्रों में अप्रवास ही उनकी परिस्थिति सुधार का साधन नहीं है। जब तक कि उन्हें रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध न कराये जायें। रोजगार केन्द्रों का पत्रावलियों के आधार पर उनका कहना है कि अधिकांश आवेदन हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त भी नहीं थे, अत्एवं उनकी शैक्षणिक स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।

Khare, H., (1981) Why Reservation? The Hindustan Times, April[68]

खरे (1981) का कथन है कि आरक्षण नीति ने हरिजनों के उत्थान में भूमिका का निर्वाह किया है। इसके माध्यम से इन्हें मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक और आर्थिक निर्योग्यताओं से दूर किया गया है लेकिन अभी भी पूरी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही इस नीति के कारण तनाव भी बढ़ा है।

Gupta, A.K., (1984) Caste Hierarch and Social Change, Jyotsana Prakashan, New Delhi.[69]

गुप्ता (1984) ने जाति श्रेणीबद्धता और सामाजिक परिवर्तन के अन्तर्सम्बन्धों की विवेचना करते हुए 20 वीं शताब्दी

में परम्परागत भारतीय समाज की संरचना में राजनीतिक परिवर्तनों के साथ-साथ जाति व्यवस्था पर आधारित भारतीय समाज में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण किया हैं अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में किये गये इस अध्ययन में विभिन्न जातियों की श्रेणी क्रमबद्धता और जनमानी व्यवस्था के के साथ-साथ शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा का मूल्यांकन किया गया है। उनका कथन है कि अनुसूचित जातियों के अधिकांश परिवार आर्थिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं। इनकी परिस्थिति में सुधार के लिए शिक्षा, आय और व्यवसाय आदि में सकारात्मक सुधार की आवश्यकता है। उनका कथन है कि हिन्दू समाज संरचना में स्वतन्त्रता के बाद उच्च स्तरीय संस्थात्मक परिवर्तन हुए हैं। भारत की नयी विधिक और राजनीतिक संरचना में जन्म पर आधारित जाति विशेष की चुनौती विहीन प्रतिफल विभिन्न व्यवसायों में अलग-अलग जातियों की संलग्नता और उसकी जीवनशैली में हुए परिवर्तन से परिवर्तित होता है।

Khare, R.S. (1984) The Untouchable of himself: Combridge University Press, Combredge.[70]

खरे (1984) ने लखनऊ के नगरीय क्षेत्र में डोम जाति की सामाजिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन करते हुए अस्पृश्यता की

अवधारणा की विवेचना की है। अपने अध्ययन के आधार पर इन्होंने नगरीय क्षेत्र में डोम जाति के परिवेश में दो वर्गों का उल्लेख किया है। एक वर्ग तो परम्परात्मक संस्थागत जाति व्यवस्था में जीवन यापन कर रहा है तो दूसरा वर्ग आधुनिक लोकतंत्र की सुविधाओं का उपभोग करते हुए राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। इन अस्पृश्य जातियों की सांस्कृतिक वैचारिकी के विश्लेषण हेतु खरे ही ने इन जातियों के सांस्कृतिक सिद्धान्तों और विधानों का विश्लेषण किया है। अपने अध्ययन के आधार पर खरे ने यह निष्कर्ष स्थापित किया है कि लखनऊ के डोम जाति में बौद्धिक और वैचारिकी माध्यमों से अपनी सांस्कृतिक निर्योग्यताओं को कुछ संदर्भों में किए विशिष्ट तरीके से दूर किया है। उनकी सामाजिक दृढ़ता ने उच्च जातियों को उनके पूर्ति परिवर्तित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए बाध्य किया है, लेकिन अधिकांश डोम जाति के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाये रखने के लिए कुछ परम्परागत प्रतीकों में उनकी हिस्सेदारी के रूप में दिखलाई पड़ता है।

Vishwanath, G. and Narsing, R., (1985) Scheduled Caste. A Study in Education Achievement, Scientific Service, Haydrabad.[71]

विश्वनाथ और नर सिंह रेड्डी (1985) ने अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक उपलब्धियों के संदर्भ में किये गये अपने अध्ययन को आन्ध्र प्रदेश की अनुसूचित जातियों पर केन्द्रित किया है। उर्ध्व सामाजिक गतिशीलता के लिए औपचारिक शिक्षा के महत्व को अनुसूचित जातियों के संदर्भ में विश्लेषित करते हुए इन्होंने यह स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि इन जातियों की परम्परागत संकुचित विचारधारा में परिवर्तन लाया जाय।

सामाजिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन के लिए इस जाति के सदस्य कभी भी सक्रिय नहीं पाये गये। अत्एवं जब तक समाज में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जायगा इन जातियों के परिस्थिति में सुधार कल्पना लगता है, और वे शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़े रहेंगे।

Vakil, A.K. (1985) Reservation Policy and Scheduled Caste in India, Ashish Publications House New Delhi.[72]

वकील (1985) ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के सन्दर्भ में किये गये अपने अध्ययन के अन्तर्गत इन जातियों के सदस्यों की शैक्षणिक एवं आर्थिक दशाओं का मूल्यांकन किया है।

इस अध्याय में प्राप्त तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि आरक्षण नीति का समय-समय पर परिशोधित किया जाना चाहिए। एक निश्चित आय स्तर वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति के सदस्यों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए वकील ने यह स्पष्ट किया कि 1978-83 की केन्द्र सरकार की योजना जो अनुसूचित जाति की आर्थिक परिस्थिति के सुधार के लिए बनायी गयी भी असफल हुई है, जिसका कारण अनुसूचित जाति के समस्याओं के निराकरण हेतु नियोजित उपायों के प्रयोग से सम्बन्धित है। केवल नौकरियों में आरक्षण और आर्थिक कार्यक्रमों में लागत दर वृद्धि कर देना ही अनुसूचित जाति के वास्तविक उत्थान का सूचक नहीं है, अपितु व्यवसायिक भिन्नताओं के कारण इन जातियों की असमान आर्थिक देशायें भी प्रमुख अवरोधक मानी जा सकती है। सामान्यत: इन जातियों के लोग निम्न स्तरीय लाभ वाले व्यवसायों में लगे हुए हैं। उनके द्वारा स्वयं नया व्यवसाय शुरू करने की स्थितियां भी आर्थिक कारणों से प्रतिबन्धित है। राज्य सरकारों की भूमि सुधार नीति भी इन जातियों के हितों को संरक्षित करने में असफल हुई है।

Sinha, R.K. (1986) Alienation Samraj Scheduled Caste, Manx Publication, Delhi.[73]

सिन्हा ने (1986) ने अनुसूचित जातियों की प्राथमिकता के सम्बन्ध में किये गये अपने अध्यय से यह निष्कर्ष प्राप्त किया है कि परम्परागत भारतीय समाज ब्रम्हणवादी व्यवस्था और हिन्दू मूल्यों तथा प्रतिमानों पर आधारित रहा है जिसमें उच्च जातियों में बहिर्जातियों के प्रति भेद-भाव अमानवीय दृष्टिकोण और शोषण की प्रवृत्तियां नीहित थी। एसी स्थिति में केवल इन जातियों के प्रति सरकारी नीतियों में होने वाले परिवर्तन नहीं है अपितु सम्पूर्ण समाज को नये युक्ति संगत आधारों पर पुनर्गठित करना होगा।

Selvanath, S, (1989) Status of Scheduled Castes, Ashish Publishing House, New Delhi[74]

सिलवानाथन (1989) ने अनुसूचित जातियों की परिस्थिति के अध्ययन हेतु तमिलनाडू राज्य के पांच जनपदों से 15 गावों और पांच कस्बों का चयन किया था। इनसे कुल 450 गृहस्थों का चयन करके अनुसूचित सामाजिक परिस्थिति के सम्बन्ध में तथ्यों का संकलन किया था। अपने अध्ययन के आधार पर सिलवानाथ ने जो निष्कर्ष प्रस्तुत किया है उससे यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति के परिवारों में कुल वस्तुओं का मूल्य के तुलना में एक तिहाई था और उत्पादकता मूल्य भी कम था। इन

परिवारों की मासिक आय अन्य जातियों की तुलना में एक तिहाई कम थी। इसमें से अधिकांश परिवार 400 रूपयों से भी कम प्रतिमाह आय करते थे। इनमें से अधिकांश परिवार 400 रूपयों से भी कम प्रतिमाह वाले परिवार थे। इनमें 8 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जो 2000 रूपये से अधिक प्रतिमाह आय करते हैं, जबकि अन्य जातियों के 26 प्रतिशत परिवार इस आय श्रेणी के थे। 54 प्रतिशत सदस्य निरक्षर थे जबकि अन्य जातियों में निरक्षण सदस्य मात्र 30 प्रतिशत थे। कृषक और कृषि मजदूरों में निरक्षरता तुलनात्मक रूप से अधिक थी, लेकिन प्रति परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की संख्या अनुसूचित जातियों और अन्य जातियों के एक जैसी थी।

Shyam Lal, K.S. Saxena (ed) (1998) Ambedkar Nagar and Nation Building Rawat Publication, New Delhi.[75]

प्रो. श्यामलाल एवं के एस. सक्सेना द्वारा सम्पादित पुस्तक Ambedkar and Nation Building में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों को डा. अम्बेडकर के विचारों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। पुस्तक के अन्तर्गत विभिन्न लेखकों ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षिक अज्ञानता आर्थिक पिछड़ापन एवं जातिगत

संस्तरण में हीन भावना आदि का विवेचन किया गया है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि इनकी दशा में सुधार तभी सम्भव है जब आरक्षण के द्वारा इन्हें विविध प्रकार के सुविधाओं को प्रदान किया जाय तथा उनके लिए विकास के द्वार तभी खुल सकते हैं जब उनके जीवन के विविध पक्षों से सम्बन्धित अभाव को दूर किया जाय।

अतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति का समाज के सवर्णो के साथ विकास तभी सम्भव है जब उन सुविधाओं को प्रदान करने की व्यवस्था की जाय जिससे वे वंचित रहे हैं।

इस प्रकार से डोम जाति के उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अभिवृत्ति एवं समस्याओं से सम्बन्धित पूर्ववर्तीय अध्ययनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि डोम जाति के लोगों के शैक्षणिक उपलब्धि आकांक्षा, व व्यवसायिक आकांक्षा और सामाजिक मूल्यों से सम्बन्धित अनुभवात्मक अध्ययनों की मात्रा कम है। पूर्वांचल व विश्व विख्यात नगरीय काशी पवित्र पावन नगर वाराणसी नगर के डोम जाति के अध्ययन से सम्बन्धित प्रस्तुत अध्ययन का महत्व सारगर्भित है।

BIBLIOGRAPHY

[1] Atal Yogesh, The Changing Frontiers or Caste, National, Delhi, 1968.

[2] Khan, Mumtaz Ali, Scheduled Caste and their Status in India uppal Publishing House, New Delhi, 1980.

[3] Louis, Wirth Urbanism as a Way of Life, "in Hatt, P.K. and Reises, A.J. (eda.) Cities and Society, The Free press, Gleneoe. 1957 P 46-73.

[4] Srinivas, M.N., Social Structure of Mysor Villages in M.N. Srinivas (ed.) India's Villages, Asia Publishing House, Bombay, 1955.

[5] Bailey, F.G. Caste and the Economics Frontier, Oxford University Press, Bombay, 1958.

[6] Roa, M.S.A., Urbanization and Social Change, Orient Longman Ltd. New Delhi, 1970.

[7] Lewis, Oscar, Village Life in Northern India, Altered A., Knopf. INC. Newyark, 1958, 781.

[8] Roy, Ajit, "A Brathan Village of Sasane Type of Purim, Orison" Man in India,Vol.36, No.1 Jan- March, 1956. P.7.

[9] Das, A.K., Occupational Patter through Generation in Rural Areas of West Bengal, Scheduled Caste and Schedule Trips welfare Deptt. Govt. of west Bengal, Calcutta, 1968, P.16.

[10] Raddy, G.P. "Caste and Change of occupation in a Village in Andhra Pradesh, The Eastern Ant horologist, vol.xx1. No2, Jan-April, 1968, P.167.

[11] Barnabas, A.P., Social Change a North Indian Village, The Indian Institute of Public, Administration, New Delhi, 1969, P.46.

[12] Beals, A.R., Social Structure and the Predication of Conflict Contribution to India Society No. 11 (ed.) Harper and others Vikash, Publication New Delhi, Dec. 1969, P.64.

[13] Sharma. H., "Caste and occupational Mobility in a Delhi Village" The Eastern Anthropologist, Vol.xx IV No. May-Aug. 1971.

[14] Gangrade, K.D., "Social Mobility in India, A Study of Depressed Class. "Man in India.

[15] Bailey, F.G., Caste and the Economics Frontier, Oxford University Press, Bombay, 1958.

[16] Reddy, G.P., "Caste and Change of occupation in a Village Eastern, Anthropologist, Vol.XX1, No.2, Jan-April, 1968

[17] Rath, S.N., "Caste and occupations sin two Per urban, Assamese Villages, Eastern, Anthropologist, vol, XXI, No.2, Jan-April

[18] Roa, M.S.A., Urbanization and Social Change, Orient Longman, Ltd., New Delhi, 1970.

[19] Beals. A.R.,(in) India's Villages M.N. Srinivas (ed.) Asia Publishing House, Bombay, 1955.

[20] Sharma, J, in M.N. Srinivas (ed.) Indias Villages Asia, Publishing House, Bombay, 1955

[21] Bailey, F.G., Caste and Economics Frontier Oxford University, Press, Bombay, 1958.

[22] Mathur, K.S., Caste and Ritualin Malwa Village, Asia Publishing House, New Delhi, 1964.

[23] Nath, V., The New Village, Impact of Change, The Economics Weekly,Vol XV11, No. 18 May, 1, 1965.

[24] Reddy, Ajit., "Caste and Change of Occupation in a Village in Andhra Prades, The Eastern Anthropologist Vol, XX1- N0.2 Jan-April, 1968.

[25]Roy, Ajit., "A Brathan in Village of Sasane type of Puri, Orrisa" Man in India, Vol.36 No.1 Jan-March, 1956.

[26] Sahay, K.N. "Caste and Occupation in a Village in Bihar, Man in India, Vol.47, No.3, July-Sep, 1967.

[27] Srivastva, S.K., "Cultural Change and Social Change among the Rigors, Man in India, Vol.53, No.1, Jan- March, 1973.

[28] D.Souza, Victor. "Changing Status of Scheduled Casts, The Economic, Weekly, vol.XV1, No.48, Dec. 1962.

[29] Parrathamma,C., "The Logic and Limits of Tradition and Economy in Village India, Indian Journal, of Social Research, Vol. X, No. 1-5, April, 1969.

[30] Baily, F.G., "Caste and the Economics Frontier, Oxford University Press, Bombay, 1958.

[31] Chawla, Amerjeet., "Political Change in Villages Manjalpur" in Sanjee, A.H. (ed.) Politics of Per urban Community in India, Asia Publishing House, Bombay, 1964.

[32] Patnayak and Laxminarayan,H.D. "Factional Politics in Village India, Man in India, Vol.149, No.2 Aug-Sep, 1969.

[33] Majumdar, D.N. and others, Intercaste Tensions in A.R. Desai,1 Rural Sociology in India, (ed.) Popular Prakashan, Bombay, 1969, P.399.

[34] Srinivas, M.N. "Caste in modern and other Essay, Asia Publishing House, Bombay, 1962.

[35] Dube, S.C., "Dominate Caste and Village Leadership paper read at the Seminar on. Trends of Change in Village India, held at Central Institute of Study and Research in Community, Development, Mussourie, India, 1961.

[36] Mahta S.R. Emerging Pattern of Rural leadership, wiley Eastern Private Limited, New Delhi, 1972.

[37] Misra, S.N. Pattern of Emerging Economics Curacy of Jamshadpur City, Patna University, Patna, 1959.

[38] Saran, P., Rural Leadership in the context of India's Modernization, Vikas Publishing House, Pvt.Ltd. New Delhi, 1978.

[39] Srinivas, M.N. Relation and Society among the Coorgs of South India, Oxford University, Press, Oxford, 1952.

[40] Gangred, K.D., "Social Mobility in India, A Study of Depressed Class" Man in India, 1975.

[41] Lewis, Oscar, Village Life in Northern India, Alfred A, Knopf, INC., Newyark, 1958.

[42] Bailey, F.G. Caste and Economic Frontier Oxford University, Press, Bombay, 1969.

[43] Beteille, Andre, Caste: Old and New Asia, Publishing House Bombay, 1959.

[44] Patel, H.L. "The France Group, Behavior of a Kshatriya" Caste in Western Indian Village, Society and Culture, Vol. 1V, No.1 Jan, 1973.

[45] Briggs, Geo.W., The Chamars, Oxford University, Press, London, 1920.

[46] Kelkar, N>C. The Elevation of the Depressed Classes Pleasures and Privileges of the Pen,

Keshinath N. Kelkar (ed) Poona, K.N. Kikar, 1929.

[47] Ambedkar, B.R. Annihilation of Caste Kadrekar Bharat Bhusan, Printing, Press, Bombay, 1939.

[48] Dutt, N.K. Origin and Growth of Caste in India, Vol.1, (2000-300Bc.) Trubner, London.

[49] Dube, Sc., India's Changing Villages Rutledge and Kaganpaul, Ltd., London, 1960.

[50] Srinivas, M.N., "Mobility in the Caste System," in (eds.) Milton Singer, Structure and Change in Indian Society and Bernard S. Cohn. Aldine Publishing Co., Chicago, 1968.

[51] Kumar, Dharma, Caste and Caste in South India, Combridge University Press, Combridge, 1965.

[52] Barnabas, A.P, "Caste in Changing India, The Institute of Public Administration, New Delhi, 1965.

[53] Agrwal, P.C., Caste Relation on Power, Shri Ram Centre, for Industrial Relations, New Delhi, 1971.

[54] Srinivas, M.N., "The Dominate Caste in Ramapura," American Anthropologist, Vol.61, No.1, 1959.

[55] Mukharjee, Radhkamal.,"Inter Caste Tension Studies, Lukhnow, University, 1951.

---

[56] Rama Swamy, V., "Self Identity among Scheduled Castes: A Study of Andhra" Economic and Political Weekly, 1974.

[57] Rao, N.V.K., Political and Social Reform and Scheduled Caste in Coatal, Andhra, Journal of Social Research 2, 1975.

[58] Sachidanand, The Harijan Elite, Thomson Press Delhi, 1977.

[59] Agrawal, P.C. and Ashraf, M.S. Equality through Privilege, A Study of Special Privilege of Scheduled Castes in Harijana, Shri Ram Centre for Industrial Relation and Human Resource, New Delhi, 1976.

[60] Singh, Y., Modernization of Tradition in India, Thomson Press, Pub., Ltd., New Delhi, 1973.

[61] Kamble, N.D. Atrocities on Scheduled Castes in Post Independent India, (15th August, 1947 to 15 August1979.) Ashish Pvt. House, New Delhi, 1981

[62] Khan, Mumtaz Ali. Scheduled Castes and their Status in India Uppal Publishing House, New Delhi, 1980.

[63] Chitnis, The Educational Problems of Scheduled Castes and Tribe Collage Student I Maharashtra, 1974.

[64] Duby, S.M. — The Study of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Collage, Student in Assam, I.C.S.S.R., 1974.

[65] Gangrade, K.D. — Educational Problems of the Scheduled Castes in Haryana(Collage Student) I.C.S.S.R., 1974.

[66] Pimply, P.N., — A Profit of Scheduled Caste Student. Panjab University Press. Chandigarh, 1980.

[67] Usha Roa, N.J. — Deprived Caste in India, Chugh Publication Allahabad, 1981

[68] Khare, H., — Why Reservation? The Hindustan Times, April, 1981.

[69] Gupta, A.K., — Caste Hierarch and Social Change, Jyotsana Prakashan, New Delhi, 1984.

[70] Khare, R.S. — The Untouchable of himself: Combridge University Press, Combredge, 1984.

[71] Vishwanath, G., Narayan,R., — Scheduled Caste, A Study in Education Achievement, Scientific Service, Haydrabad.

[72] Vakil, A.K. — Reservation Policy and Scheduled Caste in India, Ashish Publications House New Delhi, 1985.

[73] Sinha, R.K. — Alienation Samraj Scheduled Caste, Manx Publication, Delhi, 1986.

---

[74] Selvanath, S, Status of Scheduled Castes, Ashish Publishing House, New Delhi, 1989.

[75] Shyam Lal, (ed) K.S. Saxena,. Ambedkar Nagar and Nation Building Rawat Publication, New Delhi, 1998.